ग्रासरूट

मानवीय सरोकारों का दस्तावेज़

वर्ष 4 संख्या 9 | सितंबर 2003 (मासिक) | 15 रुपए

जैविक खेती अभियान की अगुआ मेदक की महिलाएं

आशीष कोठारी
(मेदक, आंध्रप्रदेश)

ज़रा कल्पना करिए उच्च योग्यता प्राप्त, डॉक्टरेट किए हुए नामी गिरामी प्रोफेसरों की बोलती बंद एक अनपढ़ देहाती किसान औरत कर दे? हाल ही में, आंध्रप्रदेश के एक छोटे से गांव में इस अविस्मरणीय वाकये का मैं चश्मदीद गवाह बना। अवसर था, मेदक जिले के एक छोटे से गांव, गंगवार में गंगवार अंजम्मा की एक कमरे की झोंपड़ी में, भारत की राष्ट्रीय जैवविविधता रणनीति और कार्ययोजना, (यानि एनबीएसएपी) बनाने की अनवरत प्रक्रिया में शामिल कई समन्वयकों और भागीदारों के पधारने का। इस राष्ट्रीय कार्ययोजना ने औपचारिक रूप से शिक्षित वैज्ञानिकों और शहर में पले–बढ़े विशेषज्ञों का क्षेत्र समझे जाने वाले जैव विविधता संरक्षण को, आज एक सही जगह पर पहुंचा दिया है और यह कुछ करने का तरीका, अंजम्मा के घर आने से बेहतर और क्या हो सकता था? आंध्र, कर्नाटक, पांडिचेरी, केरल और तमिलनाडु के शिक्षक संस्थानों के इन प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों की आंखें, तब हैरत से फटी की फटी रह गई, जब अंजम्मा ने अपने घर की एकमात्र चारपाई के नीचे से मिट्टी के बर्तनों में रखी फसलों की 50 किस्में, एक के बाद एक निकालनी शुरू कर दीं। उसने बड़ी–बड़ी टोकरियां भी दिखाई, जिनमें भीतर चारों ओर मिट्टी, राख और नीम की पत्तियों का लेप लगा हुआ था और जिनके भीतर खाद्यान्नों की कई किस्में जमा करके रखी हुई थीं। लंबे अरसे से रखे होने के बावजूद, वे कीड़ों से सुरक्षित थीं। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने ज्वार, बाजरा, रागी, धान, लिए ज़मीन का टुकड़ा और खेती के लिए ज़मीन खरीद ली। सरकारी मदद भी मिली और आज उनकी 10 एकड़ ज़मीन है, स्थानीय देवनी नस्ल के तीन–चार बैल हैं और एक छोटा सा घर है। उनके पति खेत में उनका हाथ बंटाते हैं, लेकिन जब बात बीज छांटने और उनके संरक्षण की बात आती है, तब फैसला वे और उनकी बहुएं करती हैं। वे 30–40 किस्मों को हर साल फिर से उगाती हैं। उनके विभिन्न गुणधर्मों का परीक्षण करती हैं, अच्छे बीज किसानों को देती हैं और बदले में उनसे अधिक बीज वापिस लेती हैं। इस तरह वे बीजों के चयन, उपयोग, भंडारण, पुनरोपयोग और विकासक्रम का चक्र चलाती रहती हैं। कभी कभी वे इसी खेत में सात–आठ किस्में उगाती हैं और किन किस्मों की खेती करनी हैं, यह फैसला वे सीज़न, मौसम, पिछले साल में बढ़ती पैदावार और मिट्टी की हालत पर विचार करके करती हैं।

लगती हैं न कृषि वैज्ञानिक? कृषि वैज्ञानिक से कम भी नहीं हैं वे। बस, अंतर इतना है कि हमारे प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कृषि संस्थानो और विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों के पास इसी काम के लिए अत्यंत खर्चीली परियोजनाएं होती हैं और अंत में उनमें से कई (शुक्र है सभी नहीं) संकर बीजों, सिंथेटिक कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों की पैरवी करते नजर आते हैं। वही हरित क्रांति मार्का पैरवी, जिसे भारत में खाद्य सुरक्षा का जनक माना जाता है। अंजम्मा कोई रसायन इस्तेमाल नहीं करतीं, क्योंकि वे उन्हें धरती माता के लिए ज़हर मानती हैं। उनकी किसानी वैज्ञानिक हैं, लेकिन उसमें प्रकृति के साथ गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव दृष्टिगोचर होता है। तो क्या इसीलिए वे पिछड़ी हैं.... या मेरा जैसा व्यक्ति उन्हें भारत की दिनो दिन बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए भोजन की बढ़ती ज़रूरतों के संदर्भ में उन्हें रोमांटिक तथा अयथार्थवादी होने की वजह से सम्मान देता है? क्या हरित क्रांति के बिना हम भूखों नहीं मर रहे होते?

जवाब के लिए, आइए अगले दिन सुबह के एक और दौरे की बात करें, जिस पर इस कार्ययोजना के सदस्य गए

(शेष पेज 2 पर)

स्वास्थ्यकारी विकल्प

ग्रासरूटस के इस अंक में हम मिट्टी और जल संसाधनों को कीटनाशकों से बढ़ते खतरे से बचाने के एक सुरक्षित विकल्प के रूप में जैविक कृषि पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अस्सी के दशक के मध्य से ही जैविक कृषि के पक्ष में एक आंदोलन चलता चला आ रहा है, जो दिनों–दिन जोर पकड़ता जा रहा है। उदयबीर के गन्ने के जैविक खेतों में पानी की खपत 80 प्रतिशत तक कम हो गई है। विभिन्न राज्यों में पारंपरिक बीज बैंक खुल गए हैं और जैविक रूप से उगाई गई खाद्य सामग्री दिल्ली हाट में एक बड़े पैमाने पर बिक रही है।

रागी, झंगोरा (एक किस्म की ज्वार) और अमरंथ, जो लोगों की याददाश्त से लगभग मिट ही गए थे, फिर से दिखाई देने लगे हैं। जैविक रूप से खेती केवल गेहूं, चावल, मकई और दलहनों की ही नहीं हो रही है। लाल मिर्च, धनिया और हल्दी जैसे ताजे तथा मिलावट से मुक्त मसाले और अदरक पेय, नींबू स्क्वाश, लीची स्क्वाश और पुदीना स्क्वाश जैसे शर्बत बाजार में मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में गंगवार की एक अनपढ़ किसान अंजम्मा 80 किस्मों के बीज संभाल कर रखे हुए है।

यह सच है कि जैविक रूप से उपजाई गई खाद्य सामग्री पारंपरिक तरीकों से पैदा की जाने वाली खाद्य सामग्री से महंगी होती है। इसका असली कारण यह है कि ऐसी सामग्री काफी कम मात्रा में है और फिर ऐसी जैविक खाद्य सामग्री को सब्सिडियों का सहारा भी नहीं मिलता। अगर देश भर के किसान बड़े पैमाने पर जैव कृषि करना आरंभ कर दें तो कीमतें अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी। हम अगर अपनी भावी पीढ़ी को जहरीले भोजन और पानी से बचाना चाहते हैं तो इस आंदोलन का हमें समर्थन करना होगा। इस विषय पर आलेख देखें पेज [illegible]

सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए पुरस्कार

ग्रासरूट में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ फीचर

ाओं
............10
ल
............11
से
............12
............13
............14
खाने
..........15
बनाने
...........16

भट्टाचार्जी
नू, आनंद
साद
स इंस्टीट्यूट ऑफ
ाराखंभा रोड,
001.
ष्स : 23311975;
l.net.in
roots.org
इंस्टीट्यूट ऑफ
मॉस कम्युनिकेशन
ौर प्रकाशित।

जैविक खेती अभियान की अगुआ...

(पेज एक का शेष)

थे। उसी ज़िले का यह बंदीकन्ने गांव है। आधा दर्जन औरतें हमें हरे भरे खेतों पर ले गईं। वहां वे खेती कर रही है। हिंदू और मुसलमान, कुल मिला कर 28 दलित महिलाओं के इस समूह की 24 एकड़ जमीन पर अब वे ज्वार जैसी कई किस्मों की खेती कर रही हैं। खेती की किस्मों का मेल और उनका चक्र (रोटेशन) बड़ी ही जटिल किस्म का है। यह इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि बिना रासायनिक उर्वरकों के मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, बिना कीटनाशकों के कीटों के हमले को रोका जा सके, अनाज व चारे सहित बायोमास की पैदावार को अधिकतम बढ़ाया जा सके तथा इतना ही नहीं, खेती के काम पर महिलाओं के साथ आने वाले छोटे बच्चों का भी जिनसे मन बहलता रहे। यह कार्यनीति इतनी सफल रही है कि कई पड़ोसी किसानो ने भी इन महिलाओं से जैव कृषि की ओर लौटने में मदद की गुहार की है। इनमें से कई तो बहुत बड़े किसान हैं और उन्होंने सघन रासायनिक खेती अपना ली थी, पर अब वे अपनी मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता वापिस लाना चाहते हैं।

पेच यहीं हैं। कोई शक नहीं कि अनाज की पैदावार काफी बढ़ाने में हरित क्रांति भारत के लिए मददगार सिद्ध हुई थी, लेकिन इसके लिए हमें एक जबर्दस्त कीमत चुकानी पड़ी है, जिसे हम आज भी चुका रहे हैं। पंजाब में, हरियाणा में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिट्टी मर रही है, उनकी सूक्ष्म–जीवी जैव विविधता नष्ट हो गई है, उनकी मिट्टी की उर्वरता चूस ली गई है या फिर, सिंचाई प्रधान तथा निरंतर कृषि से जमीन में जल भराव होने लगा है और वह लवणयुक्त हो गई है। यहां तथा भारत के दूसरे हिस्सों में, कीट और भी उग्र होकर लौट रहे हैं। वे अपने पूर्वजों से भी अधिक कीटनाशक प्रतिरोधी हो गए हैं। किसानो को घातक कीटनाशकों का अधिक मात्रा में छिड़काव करना पड़ता है, जिनका खर्च लगातार बढ़ रहा है, सीधे विषाक्तता के मामले बढ़ रहे हैं और भोजन में रासायनिक प्रदूषण की मात्रा ज़रूरत से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं और यही हम खा भी रहे हैं। उतना ही या उससे भी कम पैदावार के लिए और भी अधिक खर्च करने वाला किसान हताशा के कगार पर पहुंच गया है। उर्वरकों और कीटनाशकों के लिए सब्सिडियों से तथा इससे जुड़े पेट्रोलियम आयातों से देश पर पड़ने वाले असहनीय भार की बात को तो जाने ही दीजिए।

इस संदर्भ में देखें तो मेदक जिले की औरतों के पास समाधान है। एक सामुदायिक संगठन, 'डेकन डेवलपमेंट सोसायटी' के सदस्यों के रूप में करीब 75 गांवों की महिलाओं ने अपने–अपने संघ बना लिए हैं। 1985 के बाद से 10 हजार एकड़ से भी अधिक परती जमीन पर उन्होने खेती शुरू कर दी है तथा उनकी पैदावार पांच लाख किलोग्राम अनाज से बढ़ कर 25 लाख किलोग्राम हो गई है। 1996 से उन्होंने एक क्रांतिकारी अनुकरणीय वैकल्पिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित की है और उसे चला भी रही हैं। स्थानीय पैदावार, स्थानीय भंडारण और स्थानीय वितरण के सिद्धांत पर आधारित इस प्रणाली में लगभग 2500 महिलाएं शामिल हैं और उन्होंने लगभग 2500 एकड़ जमीन की उत्पादकता बढ़ा कर 8,00,000 किलोग्राम अतिरिक्त ज्वार कर ली है। इसका यह भी मतलब हुआ है कि तीन सालों में लगभग पांच लाख अतिरिक्त मजदूरियां उत्पन्न हुई हैं और 20000 मवेशियों के लिए एक नया चारा उत्पन्न हुआ है। इस गतिविधि से परियोजना में साझेदार प्रत्येक परिवार के लिए सालाना लगभग 1000 अतिरिक्त खाना पैदा हो रहा है। आज ये महिलाएं जिस ग्राम स्तरीय सामुदायिक अनाज कोष की स्थापना कर पाई हैं, वह उनके समाज में गंभीर भुखमरी के समय निर्धनतम और निराश्रित व्यक्तियों की भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करता है।

और अब उन्होंने एनबीएसएपी के तहत एक जैव विविधता कार्ययोजना बनाई है, जिसका उद्देश्य इस प्रयास को मजबूती प्रदान करना है। इस कार्य योजना की एक प्रमुख मांग यह है कि सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों और कृषि योजनाओं को नया स्वरूप देना होगा, जो रसायन प्रधान खेती की बजाय जैविक जैवविविधता वाले उत्पादों का समर्थन करें।

इस मांग या टिकाऊ खेती के लिए अभिनव प्रयासों में मेदक की महिलाएं अकेली नहीं है। हिमालय की तराई में बीज बचाओ आंदोलन, छत्तीसगढ़ में रूपांतर, कर्नाटक में ग्रीन फाउंडेशन, महाराष्ट्र में विकास विज्ञान अकादमी, विदर्भ मे जैव कपास उत्पादकों का नेटवर्क तथा कई अन्य प्रयासों से पता चलता है कि खेती का भविष्य यही है। रसायन प्रधान हरित क्रांति नहीं, टेक्नोक्रेटों की हाई बायोटेक्नोलाजी भी नहीं, बल्कि मेदक की महिलाओं की सरल, समय की कसौटी पर खरी, स्थानीय नियंत्रित, कम खर्च वाली प्रणालियां हैं। ■

(ग्रासरूट फीचर्स)